

हरियाणा दिवस पर हरियाणा निर्माण के संघर्ष में शामिल हरितियों को भूलना कितना उचित ?

हरियाणा दिवस के अवसर पर सभी हरियाणा-वासियों को गर्व है। किंतु हरियाणा निर्माण के इतिहास और उसके लिये संघर्ष करने में जिन-जिन हरितियों का योगदान रहा है, वर्तमान पीढ़ियों के नौजवानों के लिये जानना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि अगर इन लोगों ने यह संघर्ष न किया होता तो आज पूरा हरियाणा पंजाब का ही एक हिस्सा-मात्र होता। यही नहीं, सभी हरियाणा-वासियों को प्रथम भाषा के रूप में पंजाबी पहनी अनिवार्य होती और सभी परिशाओं का माध्यम भी पंजाबी होता। और उससे भी बढ़कर हरियाणा बनने के बाद जो उन्नति हरियाणा की हुई है, वह कभी ना हो पाती।

इस संघर्ष में जिन हरितियों ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनमें स्वतन्त्रता-सेनानी एवं गांधीवादी नेता बाबू मूलचन्द जैन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 1952-57 तक विधानसभा का सदस्य होते हुए बाबूजी को यह महसूस हुआ कि हरियाणावासियों के विरुद्ध पक्षपात हो रहा है। इस बात के उन्हें निरन्तर कई प्रमाण मिले कि पंजाबी क्षेत्र की तुलना में हरियाणा क्षेत्र के साथ सौतेली मां जैसा व्यवहार होता रहा है। इसलिए 1954-55 में भारत सरकार ने जब राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त किया तो बाबूजी ने अन्य हरियाणा विधायकों के साथ आयोग के सामने मजबूती से अपना पक्ष रखते हुए अपने प्रदेश 'विशाल हरियाणा' की मांग रखी। आयोग ने यह मांग तो स्वीकार नहीं की, परन्तु 1956 में बाबूजी के संयुक्त पंजाब में पी डबल्यू डी मंत्री रहते उनकी सूझ-बूझ, सक्रियता और मजबूती से अपना पक्ष रखने की वजह से जहां पैपु प्रदेश को पंजाब के साथ मिलाया गया वहीं पंजाबी और हिन्दी क्षेत्र भी भाषा के आधार पर चिन्हित कर लिये गये। यह कदम एक तरह से भविष्य में हरियाणा प्रांत के निर्माण की दिशा में नींव का पत्थर सिद्ध हुआ।

'हरियाणा ऑल पार्टी एक्शन' कमेटी का गठन : 1965 के अंत में पंजाब के जाने-माने नेता सन्त फतेह सिंह ने पंजाबी सूबे के लिये जान की बाजी लगा दी। उधर बाबूजी और हरियाणा के अधिकतर विधायक एवं प्रसिद्ध व्यक्तित्व पंजाब में हरियाणा के साथ सौतेली मां जैसा व्यवहार देखते हुए हरियाणा का अलग प्रांत चाहते थे। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये 'हरियाणा ऑल पार्टी एक्शन समिति' के नाम से अलग संगठन बनाया गया, जिसका प्रधान देवीलाल और महासचिव बाबू मूलचंद जैन को बनाया गया। इस समिति के अन्य प्रसिद्ध सदस्यों में राव जैरिन्द्र सिंह, पंडित श्रीराम शर्मा, प्रताप सिंह दौलता, चौधरी श्रीचन्द्र आदि भी थे। यद्यपि चौ देवीलाल इस समिति के अध्यक्ष थे, परंतु सभी तरह के ड्राफ्ट बनाने से लेकर आयोग के सामने अपना पक्ष रखने का दायित्व बाबूजी पर ही था।

इस समिति के अनुसार, पंजाब के कांग्रेसी



डॉ. स्वतन्त्र जैन
मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता

अत्यंत आश्चर्य व चिन्ता की बात यह रही कि पंजाब कांग्रेस के तत्कालीन प्रधान भगवत दयाल ने सभी कांग्रेसियों को धमकी दी कि 'कोई भी कांग्रेसी यदि हरियाणा बनाने का प्रचार करेगा तो उसे कांग्रेस से निकाल दिया जायेगा।' बाबूजी ने तुरन्त इसका जवाब दिया कि 'जब केन्द्रीय कांग्रेसी नेताओं ने पंजाबी सूबा बनाने के सवाल को नये सिरे से खोल दिया है, तो हर कांग्रेसी को अपनी राय देने और प्रचार करने का अधिकार है।' इस पर अलग हरियाणा प्रदेश बनाने की इच्छा रखने वाले कांग्रेसी भी संघर्ष समिति को सहयोग देने लगे और विरोध करने वाले बहुत कम कांग्रेसी रह गये।

सिक्खों की यह साजिश थी कि 'हरियाणा सहित सारे पंजाब में पंजाबी भाषा को स्कूलों में प्रथम कक्षा से ही लागू कर दिया जाये तो सारा पंजाब अपने आप ही भाषा के आधार पर पंजाबी सूबा बन जायेगा। दूसरी गहरी साजिश यह थी कि हरियाणा क्षेत्र का कुछ भाग दिल्ली में मिला दिया जाये, कुछ राजस्थान में और पंजाबी क्षेत्र से मिलते हुए, सिरसा, अम्बाला, जींद, हिसार और करनाल के काफी गांव पंजाब में मिला दिये जाएं।' हरियाणा की जनता को इन दोनों खतरों से बचना इस कमेटी का सबसे बड़ा लक्ष्य था।

बाबूजी एवं संघर्ष समिति के अन्य सदस्य इस विषय पर गम्भीरता से विचार कर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यदि सन्त फतेह सिंह ने यह स्वीकार कर लिया कि हरियाणा के स्कूलों में भी प्रथम कक्षा से ही पंजाबी पढ़ाए जाने की बात सरकार मान ले तो, वो हरियाणा सहित पंजाब को पंजाबी सूबा मान लेंगे, यह सुझाव हरियाणा क्षेत्र के हितों के विरुद्ध ही नहीं अपितु खतरनाक और हिनकारक भी था। इसलिए संघर्ष समिति ने निर्णय लिया कि समिति की ओर से एक शिष्टमंडल सन्त फतेह सिंह को मिले। फलस्वरूप बाबूजी और कुछ अन्य सदस्यों का एक शिष्ट मंडल ने अकाल तख्त पर बैठे सन्त फतेह सिंह को मिलकर हरियाणा-वासियों की चिंता बारे अपना पक्ष रखा। शिष्टमंडल की बात सुनकर सन्त फतेह सिंह ने विश्वास दिलाया कि 'हरियाणा क्षेत्र की मातृभाषा पंजाबी नहीं है, इसलिए वहां के स्कूलों के हर विद्यार्थी को पहली कक्षा से पंजाबी पढ़ाना उनके साथ घोर अन्याय होगा। ऐसे अन्याय पूर्ण सुझाव को वे कभी नहीं मानेंगे।' बाबूजी को इस बात से बहुत खुशी हुई कि सन्त फतेह सिंह हरियाणा के लोगों की भावनाओं के साथ कोई खेल नहीं खेलना चाहते, अपितु उनकी समस्या को मानवीय पहलु से हल करने के प्रयास में हैं। बाबूजी तो पहले से ही मानवीय पहलु पर जोर देते रहे हैं। सन्त फतेह सिंह के उक्त आश्वासन के बाद यह संघर्ष समिति अलग हरियाणा प्रदेश बनाने के लिए लगातार कार्य करती रही।

कांग्रेस के प्रधान भगवत दयाल व बंसीलाल का विरोध : अत्यंत आश्चर्य व चिन्ता की बात यह रही कि पंजाब कांग्रेस के तत्कालीन प्रधान भगवत दयाल ने सभी

कांग्रेसियों को धमकी दी कि 'कोई भी कांग्रेसी यदि हरियाणा बनाने का प्रचार करेगा तो उसे कांग्रेस से निकाल दिया जायेगा।' बाबूजी ने तुरन्त इसका जवाब दिया कि 'जब केन्द्रीय कांग्रेसी नेताओं ने पंजाबी सूबा बनाने के सवाल को नये सिरे से खोल दिया है, तो हर कांग्रेसी को अपनी राय देने और प्रचार करने का अधिकार है।' इस पर अलग हरियाणा प्रदेश बनाने की इच्छा रखने वाले कांग्रेसी भी संघर्ष समिति को सहयोग देने लगे और विरोध करने वाले बहुत कम कांग्रेसी रह गये।

इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने सरदार हुकुम सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन इसलिए किया कि वह भारत सरकार को रिपोर्ट करे कि समस्या का समाधान क्या है। बाबूजी भी इस कमेटी के समक्ष गवाह के रूप में पेश हुए और अलग हरियाणा प्रदेश की मांग की। इस मांग के विरोध में केवल भगवत दयाल और बंसी लाल ही पेश हुए। सरदार हुकुम सिंह कमेटी ने पंजाब प्रदेश के दो नये प्रदेश पंजाब और हरियाणा बनाने की सिफारिश की। भारत सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार किया और 1 नवम्बर 1966 को अलग-अलग दो प्रदेश पंजाब और हरियाणा बने। भगवत दयाल को हरियाणा का प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया।

भगवत दयाल का उसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना जिसका वह भरपूर विरोध कर रहे थे, हरियाणा की जनता के साथ एक क्रूर उपहास और निर्यात की एक विडम्बना ही कहा जायेगा। हरियाणा के लिये दूसरी विडम्बना यह रही कि जिन दो महानुभावों भगवत दयाल व बन्सीलाल ने हरियाणा प्रांत बनाए जाने का पुरजोर विरोध किया, उन्हीं दोनों को हरियाणा के भाग्य विधाता के रूप में कांग्रेस नेतृत्व ने पहला व दूसरा मुख्यमंत्री बना कर हरियाणा की जनता पर थोप दिया। परन्तु जिन्होंने हरियाणा प्रांत के निवासियों के प्रति अन्याय को भांपते हुए हरियाणा प्रांत बनवाने के लिये पुरजोर प्रयास किया, वे सब विरोधी समझे गये। और केन्द्रीय नेतृत्व यह सब जानते व समझते हुए और असन्तुष्ट घड़े के कड़े विरोध के बावजूद भी चुप रहा, जिसके परिणामस्वरूप बाबूजी समेत कई चोटी के कांग्रेसी विधायक कांग्रेस को अलविदा कहने पर विवश हो गये।
